ग्रीन डिपॉज़िट

[स्रोत: बिज़िनेस लाइन]

भारत में मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों, लोगों की अपर्याप्त सहभागिता और निजी बैंकों की सीमित रुचि के कारण ग्रीन डिपॉज़िट के स्वीकरण की गति मंद है।

- **ग्रीन डिपॉज़िट:** ये सौर ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और सतत् जल प्रबंधन जैसी **हरित परियोजनाओं** के **वित्तपोषण** के लिये निर्धारित ब्याज़-युक्त जमा राशि हैं।
  - जून 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सथायी निवेश को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन डिपॉज़िट हेतु एक **रूपरेखा तैयार की।**
    - हालाँकि, SBI जैसे बैंकों में इसको लेकर सीमित रुचि देखी गई है, क्योंकि उनकी ब्याज़ दरें नियमित जमाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं।
- **ग्रीन डिपॉज़िट संबंधी चुनौतियाँ:** नियमित जमा की तुलना में **ग्रीन डिपॉज़िट पर कम ब्याज़ दरें ग्राहकों को हतोत्साहित करती हैं।**
  - बैंकों को यह परिभाषित करने में कठिनाई होती है कि कौन सी गतिविधियाँ **"हरित" मानी जाएंगी तथा हरित निवेश के लिये स्पष्ट रूपरेखा का भी अभाव है।**
  - ग्रीन डिपॉज़िट के लिये आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) की आवश्यकता अधिक है, जो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में बाधा बन सकती है।
- **ग्रीन डिपॉज़िट के प्रति भारत की प्रतिबद्धता:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की पूर्ति करना है तथा इस परिवर्तन में **हरित वित्त महत्त्वपूर्ण होगा।**

और पढ़ें: RBI का ग्रीन डिपॉज़िट फ्रेमवर्क

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/green-deposits-1